1

LOK SABHA

Wednesday, August 9, 1978/Sravana 18, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फरक्का में तापीय विद्युत संयंत्र

*344. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने फरक्का में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) यदि स्वीकृति दी गई है तो इसके निर्माण-कार्य पर कुल कितना समय लगेगा और इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी, और

(घ) इसके लिए बिजली-उत्पादन क्षमता का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P RAMACHANDRAN) (a) to (d) With a view to setting up a large sized thermal station at Farakka, the National Thermal Power Corporation prepared a feasibility report for the techno-economic clearance of the project by the Central Electricity Authority The proposal is to instal a capacity of 1100 MW at Farakka for meeting a part of the power requirements of the Eastern Region

The techno-economic examination has been completed and preliminary survey work has already been started by NTPC The proposal will be submitted for investment clearance shortly.

2

According to the project report, it will be possible to commission 1100 MW capacity by 1985-86 and the likely expenditure for the first phase of 1100 MW is estimated to be of the order of Rs 456 crores

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल राष्ट्रीय महत्व का नहीं है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का रहा है। वास्तव में हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि कांग्रेस सरकार ने जो यह योजना खटाई में डाल रही थी उसके बारे में हमारी सरकार ने निर्णायक बिन्दु पर पहुंच कर राष्ट्रीय भलाई के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जाएगा इस विषय में सदन को सही जानकारी मंत्री जी दें क्योंकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के विषय में यह विशेष रूप से देखा जाता है कि जो निर्णय लिए जाने हैं इतनी लम्बी अवधि तक उनको टाला जाता है कि उस बीच में कोस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है परिणामस्वरूप उसके ऊपर राष्ट्र का बहुत अधिक पैसा व्यय हो जाता है और राष्ट्र के सामने विद्युत् की आइसिस चली आती है उसके समाधान में भी देर लग जाती है। इस बारे में जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

SHRI P RAMACHANDRAN. This project, even though it is delayed a little bit, all the preliminary works are going on and there is no difficulty in processing this project Unfortunately, certain problems have to be sorted out before this project is started The coal has to be linked Earlier the previous Governments had not prepared the project reports for the coal linkage also So, we have to do some investigation with regard to the availability of coal and also the mode of transport from the place of coal availability to the power station Also some clearance has to come from various other sectors. That is why it has taken a little bit of time But I can tell the hon House that all the things are being done expeditiously, and that very soon, a

decision will be taken to start the production.

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय मंत्री जी इस विषय में जानकारी दें जैसा कि उनकी रिपोर्ट के द्वारा मालूम पड़ता है कि 1100 मेगावाट विद्युत का इसमें उत्पादन होगा तो क्या इसमें से कुछ अंश हम लोगों को बंगला देश के लिए भी देना होगा ? यदि देना होगा, तो क्या उस अंश की हमें कुछ पूंजी प्राप्त होगी हैं इस पर जितनी पूंजी का इन्वैस्टमैंट होने जा रहा है क्या वह हमारे राष्ट्र द्वारा ही व्यय किया जा रहा है या किसी अन्य वर्ल्ड बैंक एजेंसी के द्वारा धन की प्राप्ति हो रही है ? इसमें जो सारा तकनीकी कार्य हो रहा है, वह हम अपने इंजीनियरों से करवा रहे हैं या किसी अन्य कंट्री के कोलैबोरेशन से इस कार्य को पूरा करेंगे ?

SHRI P. RAMACHANDRAN. I do not know how the hon. Member has got impression about Bangladesh. This station is meant for the eastern region in our own country. The question of Bangla desh does not arise. About the seond part of the question we are trying to get certain facilities from the World Bank also and the moment the project report is completed and the investment decision is taken. we will pose it to the World Bank Then we will get the necessary funds for it.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Will the equipments for the Farakka plant be secured from our own country, viz from BHEL—and even MAMC (Durgapur) can produce some electrical equipments. Will these equipments be secured from within our own country? And, in view of the reply given earlier, the shortage of electricity will continue upto 1985-86. In view of these facts, will the Government consider the construction of another power plant in the Raniganj area, which is in the pithead of the coal belt?

MR. SPEAKER: The later part of the question does not arise. Only the first part arises.

SHRI P. RAMACHANDRAN: With regard to this Farakka power station, this station. when completed, will generate 1100 megawatts of power. With regard to the shortage of power in West Bengal, steps are already being taken to remove these shortages. Once this project is completed, there will not be any shortage of power in the eastern region, and also in West Bengal.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI: So far as coal linkage was concerned, I remember that in the previous session, the hon. Minister said that there were some coal available very near Farakka in Santal Parganas. Is that fact also taken into account and the Plan being made, ready, keeping that also in view?

SHRI P. RAMACHANDRAN: For this large power station, we require lot of coal. That is why we are trying to link this power station with the Rajmahal coal fields, where there is enough coal reserves for a larger power station That is why we are trying to link it with the Rajmahal coal fields; and we are trying to identify the mode of transport and other facilities required for the setting up of this thermal power station.

राष्ट्रीय परमिट योजना

*345. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रकों के लिये वर्तमान राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में प्रत्येक डिवीजन के अधिकारी निर्धारित संख्या में ही ट्रकों को अन्तर्राज्यीय परमिट देते हैं जिससे भ्रष्ट आचरण की अधिक सम्भावना है, और

(ख) क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सरकार का विचार उन सभी ट्रकों के लिये, जो वर्ष 1976-77 के नवीनतम माडल के हैं अन्तर्राज्यीय परमिट देने के लिए कोई निर्णय लेने का है ताकि अधिकारियों को निर्धारित संख्या में ट्रकों के परमिट देने में पक्षपात अथवा भेद-भाव बरतने की कोई गुंजाइश न रहे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।